JANMABHOOMI GROUP

वर्ष : २४, अंक : २४

आर्थिक और व्यापार विषयक साप्ताहिक

विमान सरचार्ज गुजरात राज्य में ५० पैसा, भारत के अन्य स्थानों पर १ रुपया

http://www.janmabhoominewspapers.com

।। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी ।।

व्यापार

REGD No. MH/MR. SOUTH-46/2009-11 RNI No. 43892/87

VYAPAR, MUMBAI मुंबई, ६ सितम्बर से १२ सितम्बर, २०१० पृष्ठ संख्या : १० मूल्य : रु. ४.००

सीजनल ग्राहकी शुरू होने से चहल-पहल बढ़ी पृष्ठ १०...

पृष्ठ ४ संपादकीय : उलझन और समीक्षा की समस्या बढ़ेगी

पृष्ठ ५ आपको सोना में क्यों निवेश करना चाहिए

पृष्ठ ७ मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास के पथ पर अग्रसर

पृष्ठ ८ ट्रैक्टर पुर्जे को वैट से मुक्त करने की मांग

खाद्य मुद्रास्फीति बढ़कर १०.८६ प्र.श.

नई दिल्ली। गत दो सप्ताह की गिरावट के बाद २१ अगस्त को समाप्त सप्ताह में सब्जियों के भाव में गिरावट के बावजूद वार्षिक खाद्य मुद्रास्फीति मामूली बढ़कर १०.८६ प्र.श. हुई।

१४ अगस्त को समाप्त सप्ताह में खाद्य मुद्रास्फीति उससे पूर्व सप्ताह के १०.३५ प्र.श. से घटकर १०.०५ प्र.श. रही। शुक्रवार को जारी अधिकृत आंकड़े के अनुसार वार्षिक आधार पर आलू ५१ प्र.श. सस्ता हुआ है जबकि कुल मिलाकर सब्जियों में ९.९० प्र.श. की गिरावट आयी। प्याज की कीमत में भी ८.९७ प्र.श. की गिरावट आयी। मुख्यत: गत वर्ष की समान अवधि की तुलना में दाल, चावल एवं गेहूं का भाव बढ़ने से अनाज के भाव में ६.७६ प्र.श. वृद्धि हुई। दाल के भाव में १४ प्र.श., चावल में ८.०५ प्र.श. एवं गेहू के भाव में ७ प्र.श. की वृद्धि हुई। अन्य खाद्य आयटमों में दूध के मूल्य में १८.२२ प्र.श. और फलों के भाव में ९.२७ प्र.श. की वृद्धि हुई। वर्ष में अधिकांश समय मुद्रास्फीति दो अंक में बनी रही।

एक दशक बाद भी लोकप्रिय नहीं हुई सोने के जेवरात पर हॉलमार्किंग योजना

बीआईएस एक्ट में संशोधन कर योजना को अनिवार्य करने पर विचार

प्रवीण राणा

नई दिल्ली । देश में सोने के आभूषणों की शुद्धता के प्रमाण के लिए स्वैच्छिक आधार पर शुरू की गई हालॅमार्किगं योजना एक दशक बीत जाने के बाद भी लोकप्रिय नहीं हो पाई है जबकि देश में सर्वाधिक जेवरात की खरीद-बिक्री होती है। देश भर में मात्र १४७ हॉलमार्किगं केन्द्र खुल पाए हैं और लगभग ३३ लाख ज्वैलर में से केवल ७१८५ ने भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) से हॉलमार्किगं का लाईसेंस लिया हुआ है।

स्वैच्छिक आधार पर असफल नहीं इस योजना को अब चरणबद्ध ढंग से अनिवार्य किए जाने पर पुन: विचार हो रहा है और इसके लिए सरकार बीआईएस एक्ट १९८६ में संशोधन करने के लिए विधेयक लाने की तैयारी कर रही है।

जेवरात की शुद्धता के लिए तीसरे पक्ष के प्रमाणन के लिए वर्ष २००० में स्वैच्छिक आधार पर यह योजना शुरू की गई। इस योजना का मुख्य मकसद उपभोक्ता को घटिया क्वालिटी के जेवरात की खरीद से बचाना तथा देश को सोने के आभूषणों की मार्किट का अग्रणी केन्द्र बनाकर निर्यात बढाने के लिए ज्वैलरी उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना था।

३३ लाख ज्वैलर: ७१८४ ने लिया लाईसेंस

लेकिन एक दशक के बाद भी १७ राज्यों में मात्र १४७ हॉलमार्किगं केन्द्र खुल पाए हैं और देश के लगभग ३३ लाख ज्वैलर में से केवल ७१८५ ने भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) से हॉलमार्किगं का लाईसेंस लिया हुआ है। बाकि के राज्यों में अभी तक ऐसे कोई केन्द्र नहीं खुले हैं। कम ज्वैलरों के पास लाईसेंस होने से हॉलमार्किगं केन्द्रों को पर्याप्त काम नहीं मिल पा रहा है । इस लिए नए केन्द्र नहीं खुल रहे हैं। सरकार ऐसे केन्द्र खोलने के लक्ष्य को पूरा करने में नाकामयाब रहीं है जबकि सरकार मशीनरी और इक्यूपमेंट के लिए केन्द्र सरकार १५ लाख रूपए की सहयाता देती है। उत्तर पूर्व के राज्यों तथा विशेष केटेगरी के राज्यों के लिए यह राशि ३० लाख रूपए है।

देश में पर्याप्त मात्रा में हॉलमार्किगं केन्द्र नहीं होने की वजह से सरकार इस योजना को अनिवार्य नहीं कर पा रही है। इसलिए सरकार इस योजना चरणबद्ध ढंग से अनिवार्य करने पर विचार कर रही है फिलहाल पहले चरण में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एवं चेन्नई जैसे महानगरों में ही इसे अनिवार्य किए जाने पर विचार हो रहा है।

पहले इस योजना को पहली जनवरी २००८ से चरणबद्ध ढंग से अनिवार्य किए जाने का प्रस्ताव था लेकिन इसके लिए बीआईएस एक्ट १९८६ में संशोधन के लिए विधेयक तैयार नहीं हो पाया था। अब सरकार इस एक्ट में सशोधन के लिए विधेयक तैयार कर रही है। इसके लिए कानून मंत्रालय से स्वीकृति मिल चुकी है और वाणिज्य एवं उद्योग तथा वित्त मंत्रालय से परामर्श किया जा रहा है। पहले चरण में दिल्ली,

(शेष पृष्ठ २ पर)

Advt.

Advt.

कांग्रेस का वामपंथी नीति की तरफ झुकाव

दीवाने ख़ास

-कुन्दन व्यास

कांग्रेस के नेता प्रधानमंत्री और सरकार की नीतियों पर सार्वजनिक में प्रहार कर रहे हैं। इसे देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस दल में अब सरकार का विरोध करती वामपंथी लाबी बन रही है। राहुल गांधी भी लोकप्रिय वामपंथी नीति की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। इसे देखते हुए भविष्य में यह गंभीर मतभेद में परिणत होगा।

केन्द्र सरकार सलामत है लेकिन राष्ट्रहित खतरे में है। नक्सलवाद की चुनौती गंभीर है। लेकिन अधिक गंभीर चिन्ता हमारे पड़ोसी-पाकिस्तान और चीन के संयुक्त षड्यंत्र की है। फिलहाल यूपीए सरकार कितनी जागरूक और सक्रिय है? वस्तुत: कांग्रेस के अध्यक्षपद पर श्रीमती सोनिया गांधी सर्वसम्मति से चुनी जा सकती हैं, लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए सरकार में एकवाक्यता और एकता नहीं है। कांग्रेस में सोनिया गांधी आसानी से अध्यक्षपद पर चौथी बार चुनी गयी तथा १२५ वर्ष के कांग्रेस के इतिहास में नया कीर्तिमान स्थापित कर सकती हैं लेकिन इससे कांग्रेस और सरकार में सबकुछ ठीकठाक है ऐसा दावा कोई कर नहीं सकता। वास्तविकता तो यह है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नाम पर ही एकता है- यदि इनके नाम मैदान में न हो तो निश्चित धमाचौकड़ी होती! सोनिया गांधी कांग्रेस की सर्वेसर्वा रहेगी तो ही भविष्य में राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद पर आसीन हो सकते हैं, यह भी स्वीकार करना चाहिए। वस्तुत: राजनीति में रंग बदलते देर नहीं लगती।

बहरहाल जो समाचार आ रहे हैं एवं आसार नजर आते हैं वे अच्छे नहीं हैं। कश्मीर में भारत विरोधी विद्रोह शांत होने का आसार दिखाई नहीं देता। राजनीतिक समाधान की बातें की जाती हैं लेकिन अलगाववादियों को वह स्वीकार नहीं है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी नियंत्रण के तहत कश्मीर क्षेत्र में चीनी सैनिकों की छावनियां स्थापित की जा रही हैं।

(शेष पृष्ठ २ पर)

कपास निर्यात के विरोध में कपड़ा उद्योग द्वारा हड़ताल की चेतावनी

प्रवीण राणा

नई दिल्ली । कपड़ा उद्योग ने कपास निर्यात के मुद्दे पर चेतावनी दी है कि यदि उद्योग के हित में फैसला नहीं किया गया तो स्पीनर्स से लेकर गारमेंट तक सम्पूर्ण सेगमेंट इसके विरोध में हड़ताल कर देगा।

देश के १४ टेक्सटाइल संगठनों ने प्रधानमंत्री, वित्त, वाणिज्य, कृषि एवं टेक्सटाइल सचिव तथा आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमेन तथा योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भेजे संयुक्त प्रतिनिधित्व में कहा है कि वर्ष २०१०-११ में घरेलू उद्योग की जरूरत के अतिरिक्त कपास की उतनी ही मात्रा के निर्यात की अनुमति दी जाए जितनी सरप्लस है । सरप्लस मात्रा का निर्णय तत्काल वर्तमान आंकड़ों के आधार पर (शेष पृष्ठ २ पर)

सोयाबीन की होगी बम्पर पैदावार : सोपा

इंदौर। कुल बोआई क्षेत्र में ४ प्रतिशत की गिरावट के बावजूद सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन आफ इंडिया (सोपा)ने इस सीजन में ९० लाख टन सोयाबीन का उत्पादन होने का अनुमान व्यक्त किया। सोपा के संयोजक राजेश अग्रवाल ने कहा कि प्रमुख सोयाबीन उत्पादक राज्यों में फसल की स्थिति काफी अच्छी है और सब कुछ ठीक रहने पर वर्तमान खरीफ सीजन में यह ९० लाख टन के स्तर को पार कर जाएगा।

उन्होंने कहा कि यद्यपि कुल उत्पादन का ठीक अनुमान कुछ समय बाद किया जाएगा। गत वर्ष सोयाबीन का कुल उत्पादन ९७.२५ लाख टन हुआ। इस खरीफ के दौरान (शेष पृष्ठ २ पर)

Advt.